

भारत में जनजातीय शिक्षा की समस्याएँ एवं उनके समाधान हेतु सुझाव—एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (जनपद बहराइच के विशेष सन्दर्भ में)

राजेन्द्र सिंह¹

¹शोध छात्र, शिक्षाशास्त्र विभाग, किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बहराइच

Received: 20 March 2026 Accepted & Reviewed: 25 March 2026, Published: 31 March 2026

Abstract

भारत एक विविधताओं से भरा देश है, जहाँ विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति और परंपराएँ साथ-साथ विद्यमान हैं। इनमें जनजातीय समुदाय भारतीय समाज की आधारभूत और प्राचीन इकाइयों में से हैं, जो अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक पहचान रखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार ने जनजातीय विकास के लिए अनेक योजनाएँ प्रारंभ कीं, किन्तु शिक्षा का क्षेत्र अभी भी इन समुदायों में पिछड़ा हुआ है। जनपद बहराइच, जो उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती और अर्धवनाच्छादित क्षेत्र है, यहाँ बड़ी संख्या में थारू, मुसहर, कोल और खरवार जैसी जनजातियाँ निवास करती हैं। इनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण शिक्षा का प्रसार यहाँ धीमी गति से हुआ है। इस शोध का उद्देश्य बहराइच जिले की जनजातीय शिक्षा की वास्तविक स्थिति का विश्लेषण करना, शिक्षा में आ रही प्रमुख बाधाओं की पहचान करना, तथा उनके समाधान हेतु व्यवहारिक सुझाव प्रस्तुत करना है। शोध से यह स्पष्ट हुआ कि यहाँ शिक्षा की स्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं—

भौगोलिक दुर्गमता, गरीबी, शिक्षकों की अनुपलब्धता, भाषा और संस्कृति का अंतर, तथा सरकारी योजनाओं की सीमित पहुँच। जहाँ भी स्थानीय भाषा में शिक्षण, छात्रवृत्ति, छात्रावास सुविधा और सामुदायिक भागीदारी जैसे उपाय किए गए हैं, वहाँ शिक्षा में सुधार देखा गया है। यह अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि जनजातीय शिक्षा के वास्तविक उन्नयन के लिए केवल सरकारी योजनाएँ पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी, शिक्षक-संवेदनशीलता और स्थानीय संस्कृति पर आधारित शिक्षा-पद्धति अपनाना आवश्यक है।

कुंजी शब्द— जनजातीय शिक्षा, बहराइच, थारू जनजाति, शिक्षा की समस्याएँ, सरकारी योजनाएँ, सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ, समाधान—सुझाव।

Introduction

भारत की पहचान उसकी विविधता में निहित है। यहाँ सैकड़ों जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनकी जीवनशैली, परंपराएँ, भाषा और संस्कृति उन्हें अन्य समुदायों से अलग पहचान देती हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में लगभग 8.6 प्रतिशत लोग अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं (जनगणना 2011)। जनपद बहराइच में भी जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत उल्लेखनीय है, विशेषकर मोतीपुर, कैसरगंज, मिहीपुरवा, रूपैडिहा और नानपारा ब्लॉकों में थारू जनजाति का प्रभुत्व है। जनजातीय समाज की प्रगति का सबसे सशक्त माध्यम शिक्षा है, क्योंकि यह न केवल ज्ञान का विस्तार करती है बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक जागरूकता का आधार भी बनती है। किन्तु बहराइच जिले में जनजातीय शिक्षा की स्थिति अभी भी चिंताजनक है। यह क्षेत्र नेपाल की सीमा से लगा हुआ, वनाच्छादित एवं भौगोलिक रूप से दुर्गम है, जिससे यहाँ के कई गाँव आज भी मूलभूत शैक्षिक सुविधाओं से वंचित हैं।

2. अध्ययन की पृष्ठभूमि— स्वतंत्रता के बाद से केंद्र और राज्य सरकार ने जनजातीय शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए अनेक योजनाएँ चलाई जैसे—जनजातीय उपयोजना, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, समग्र शिक्षा अभियान, प्राथमिक शिक्षा सुधार कार्यक्रम, इत्यादि। फिर भी बहराइच जिले के थारू और अन्य जनजातीय बच्चों में विद्यालय उपस्थिति, साक्षरता दर और शैक्षणिक उपलब्धि अपेक्षाकृत कम है।

UDISE 2021–22 के अनुसार, बहराइच की कुल साक्षरता दर लगभग 62.7% है, जबकि थारू बहुल ब्लॉकों में यह 50–55% के बीच है। जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति और भी कमजोर है। मुख्य कारण हैं — आर्थिक निर्धनता, परिवार की असहयोगी मानसिकता, बाल श्रम, शिक्षकों की कमी, तथा शिक्षा में सांस्कृतिक असंगति।

3. अध्ययन का औचित्य— बहराइच जिले का अधिकांश जनजातीय क्षेत्र नेपाल सीमा के समीप वनों से घिरा हुआ है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि, वनोपज—संग्रह और श्रम कार्य हैं। जनजातीय समुदायों में शिक्षा को लेकर अभी भी जागरूकता का अभाव है। कई अभिभावक बच्चों को आर्थिक सहयोग के लिए खेतों या मजदूरी में लगाते हैं। स्कूलों की दूरी और सड़क—सुविधा की कमी के कारण भी बच्चों का विद्यालय जाना कठिन है। यह शोध इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह जनपद बहराइच की स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह समझने का प्रयास करता है कि शिक्षा की पहुँच यहाँ कितनी है, कौन-कौन सी वास्तविक समस्याएँ बच्चों के स्कूल जाने में बाधा बनती हैं, और कौन-सी रणनीतियाँ इन समस्याओं को दूर कर सकती हैं।

4. शोध समस्या— भारत में जनजातीय शिक्षा की स्थिति सामान्यतः पिछड़ी हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में यह स्थिति और अधिक गंभीर है।

अध्ययन का मुख्य प्रश्न यह है— “जनपद बहराइच के जनजातीय समुदायों में शिक्षा के विकास में कौन-कौन सी प्रमुख बाधाएँ हैं, और उन्हें दूर करने के लिए कौन से व्यावहारिक उपाय अपनाए जा सकते हैं?”

5. शोध की आवश्यकता— यह अध्ययन इसीलिए आवश्यक है क्योंकि शिक्षा ही वह माध्यम है जो जनजातीय समुदायों को गरीबी, सामाजिक पिछड़ेपन और अशिक्षा के चक्र से बाहर निकाल सकती है। बहराइच की जनजातियों में शिक्षा के माध्यम से न केवल आर्थिक सुधार की संभावना है बल्कि सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक भागीदारी भी बढ़ सकती है। शोध यह पता लगाने का प्रयास करेगा कि—

1. यहाँ की जनजातियाँ शिक्षा के प्रति कितना रुझान रखती हैं।
2. सरकारी योजनाएँ इन समुदायों तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुँच रही है।
3. और किन सुधारात्मक उपायों से इनकी शिक्षा को सशक्त बनाया जा सकता है।

6. अध्ययन के उद्देश्य—

1. बहराइच जिले में जनजातीय शिक्षा की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना।
2. जनजातीय बच्चों की शिक्षा में आने वाली प्रमुख बाधाओं की पहचान करना।
3. स्थानीय तथा राष्ट्रीय योजनाओं के प्रभाव का विश्लेषण करना।
4. जनजातीय समाज में शिक्षा के प्रति अभिभावकों और समुदाय के दृष्टिकोण को समझना।
5. जनजातीय शिक्षा के सुधार हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

7. अध्ययन की सीमा— यह अध्ययन विशेष रूप से जनपद बहराइच के चयनित ब्लॉकों – मिहींपुरवा, कैसरगंज, नानपारा और रूपैडिहा – पर केंद्रित रहेगा। शोध गुणात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है तथा द्वितीयक स्रोतों (सरकारी रिपोर्टें, शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट, जिला सांख्यिकी, पूर्व शोध) से प्राप्त आँकड़ों पर आधारित रहेगा। क्षेत्रीय सर्वेक्षण और साक्षात्कारों से पूरक जानकारी ली जा सकती है।

शोध विधि—

1. शोध की प्रकृति— यह अध्ययन गुणात्मक और विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। इसमें तथ्यों का संकलन, क्षेत्रीय अवलोकन, सरकारी रिपोर्टों का विश्लेषण तथा साहित्यिक समीक्षा के माध्यम से निष्कर्ष प्राप्त किए गए हैं। अध्ययन का उद्देश्य आँकड़ों की गणना नहीं, बल्कि जनजातीय शिक्षा की गुणात्मक स्थिति और वास्तविक समस्याओं को समझना है।

2. अध्ययन क्षेत्र— यह शोध जनपद बहराइच (उत्तर प्रदेश) पर केंद्रित है, विशेष रूप से उन ब्लॉकों पर जहाँ जनजातीय जनसंख्या अधिक है – मिहींपुरवा (मोतीपुर), कैसरगंज, नानपारा, रूपैडिहा ये क्षेत्र थारू, मुसहर, कोल और खरवार जैसी जनजातियों की प्रमुख बसावट वाले हैं। यह चयन इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति कमजोर है और शिक्षा की पहुँच सीमित पाई जाती है।

3. शोध की जनसंख्या— इस अध्ययन की जनसंख्या में वे सभी व्यक्ति शामिल हैं जो जनजातीय शिक्षा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं –

1. जनजातीय विद्यार्थी (प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक)
2. अभिभावक
3. शिक्षक और विद्यालय प्रबंधक
4. स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी
5. सामाजिक कार्यकर्ता एवं एनजीओ प्रतिनिधि

4. नमूना चयन विधि— चूँकि यह गुणात्मक अध्ययन है, इसलिए इसमें उद्देश्यपूर्ण नमूना चयन विधि अपनाई गई है। शोधकर्ता ने प्रत्येक चयनित ब्लॉक से कुछ विद्यालयों और समुदायों का चयन किया ताकि क्षेत्रीय विविधता का प्रतिनिधित्व हो सके।

ब्लॉक	चयनित विद्यालय	सर्वेक्षित परिवार
मिहींपुरवा	4	5
नानपारा	3	2
कैसरगंज	1	1
रूपैडिहा	2	2

कुल 10 विद्यालयों और 10 परिवारों से प्राथमिक जानकारी ली गई।

5. डेटा के स्रोत—

- i. **प्राथमिक स्रोत** – शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थियों से साक्षात्कार, क्षेत्रीय अवलोकन, पंचायत और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से अनौपचारिक वार्ता, विद्यालयों का भौतिक निरीक्षण।

- ii. **द्वितीयक स्रोत**— शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की न्वैः रिपोर्ट (2021–2023), थारू विकास योजना एवं राज्य सरकार की वार्षिक रिपोर्टें, शैक्षणिक जर्नल, पूर्व शोधपत्र, और नीतिगत दस्तावेज, जनगणना 2011 और जिला सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़े ।

6. डेटा संकलन की तकनीक—

- साक्षात्कार पद्धति**— विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से अर्ध-संरचित प्रश्नों के माध्यम से जानकारी प्राप्त की गई ।
- प्रश्नावली पद्धति**— कुछ सीमित विद्यालयों में विद्यार्थियों से शिक्षा, दूरी, और अभिभावक दृष्टिकोण से संबंधित प्रश्न पूछे गए ।
- अवलोकन**— विद्यालयों की भौतिक स्थिति, उपस्थिति रजिस्टर, और शिक्षण प्रक्रिया का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया गया ।
- दस्तावेज विश्लेषण**— रिपोर्टें और योजनाओं का तुलनात्मक विश्लेषण कर शिक्षा की स्थिति का मूल्यांकन किया गया ।

7. डेटा विश्लेषण की प्रक्रिया— संकलित जानकारी को विषयवार वर्गीकृत किया गया — जैसे आर्थिक, भौगोलिक, शैक्षणिक, और सांस्कृतिक समस्याएँ । फिर इन तथ्यों का गुणात्मक विश्लेषण किया गया ताकि शिक्षा की वास्तविक स्थिति और समस्याओं के बीच संबंध स्थापित किया जा सके । डेटा का सांख्यिकीय विश्लेषण सीमित स्तर पर (प्रतिशत और अनुपात के रूप में) किया गया ।

8. अध्ययन की सीमाएँ—

- यह अध्ययन केवल जनपद बहराइच तक सीमित है अन्य जिलों की तुलना नहीं की गई ।
- सर्वेक्षण का क्षेत्र सीमित (10 विद्यालय) रहा, जिससे परिणामों का सामान्यीकरण सीमित है ।
- उपलब्ध आँकड़ों पर आंशिक रूप से निर्भरता रही क्योंकि कई सरकारी डेटा अद्यतन नहीं थे ।
- महामारी के बाद विद्यालयों की स्थिति में हुए परिवर्तनों का प्रभाव आंशिक रूप से ही सम्मिलित किया गया ।

9. शोध की उपयोगिता— यह अध्ययन नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और समाजसेवियों के लिए उपयोगी है क्योंकि यह जनजातीय शिक्षा की वास्तविक समस्याएँ उजागर करता है, स्थानीय स्तर पर नीतियों के क्रियान्वयन की खामियाँ दिखाता है, और भविष्य के सुधार हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करता है । इसके निष्कर्षों का उपयोग जनपद बहराइच की शिक्षा योजनाओं के पुनर्निर्माण में किया जा सकता है ।

अध्याय 2 : जनपद बहराइच में जनजातीय शिक्षा की वर्तमान स्थिति

1. भौगोलिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि— जनपद बहराइच उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित है, जो नेपाल की सीमा से सटा हुआ है । यह क्षेत्र अर्धवनाच्छादित, कृषि प्रधान तथा बहुसांस्कृतिक क्षेत्र है । यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ — थारू, मुसहर, कोल, खरवार, पासी और चौरासी — सामाजिक रूप से पिछड़ी और आर्थिक रूप से कमजोर हैं । थारू जनजाति विशेष रूप से मिर्हीपुरवा (मोतीपुर), नानपारा, कैसरगंज, और रूपैडिहा ब्लॉकों में निवास करती है । इन क्षेत्रों में साक्षरता दर राज्य औसत से काफी कम है, और प्राथमिक विद्यालयों

की पहुँच सीमित है। बहराइच का लगभग 13% क्षेत्र वन भूमि से आच्छादित है। ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में बसे जनजातीय समुदायों तक शिक्षा का प्रसार करना एक बड़ी चुनौती है।

2. साक्षरता दर और शैक्षिक प्रगति— भारत की जनगणना 2011 और UDISE+ 2022–23 की रिपोर्ट के अनुसार –

श्रेणी	साक्षरता दर (%)
राष्ट्रीय औसत	74.00
उत्तर प्रदेश औसत	67.70
बहराइच जिला औसत	62.70
थारु जनजाति (अनुमानित)	52-55
जनजातीय महिलाएँ (अनुमानित)	45-48

यह आँकड़े दर्शाते हैं कि बहराइच में जनजातीय समाज शिक्षा के मामले में राष्ट्रीय औसत से लगभग 20% पीछे है। जनजातीय बच्चों का विद्यालयों में नामांकन तो बढ़ा है, परंतु उपस्थिति और परिणाम स्तर अत्यंत निम्न है। प्राथमिक स्तर पर नामांकन के बाद माध्यमिक स्तर तक पहुँचने वाले विद्यार्थियों की संख्या घट जाती है।

3. विद्यालयों की स्थिति— जिले में कुल 3200 से अधिक प्राथमिक विद्यालय हैं, लेकिन जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालयों की दूरी औसतन 3 से 5 किलोमीटर है। कई विद्यालयों में शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं या नियमित रूप से नहीं पहुँचते। विद्यालय भवनों की स्थिति कमजोर है, पुस्तकालय, प्रयोगशाला या खेलकूद सुविधाएँ नगण्य हैं, अधिकांश विद्यालयों में बिजली या डिजिटल संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। शिक्षण माध्यम प्रायः हिंदी है, जबकि थारु समुदाय की अपनी थारु भाषा और उपभाषाएँ हैं। इस भाषाई अंतर के कारण बच्चे विषयों को समझ नहीं पाते और पढ़ाई से दूरी बना लेते हैं।

4. सरकारी योजनाएँ और पहलें (बहराइच में क्रियान्वयन)

- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय—जिले में एक मॉडल विद्यालय मिर्हीपुरवा ब्लॉक में स्थापित है, जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। हालांकि सीटें सीमित हैं और प्रवेश प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी है।
- समग्र शिक्षा अभियान – प्रारंभिक शिक्षा को सशक्त करने हेतु लागू, परंतु जनजातीय क्षेत्रों में इसका वास्तविक प्रभाव सीमित है।
- छात्रवृत्ति योजनाएँ— अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक से उच्च शिक्षा स्तर तक छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध हैं, परंतु जागरूकता की कमी के कारण कई बच्चे इसका लाभ नहीं ले पाते।
- मिड-डे मील योजना— विद्यालय उपस्थिति बढ़ाने में सहायक, किन्तु गुणवत्ता और नियमितता में सुधार की आवश्यकता है।

5. 'थारु विकास योजना' (उत्तर प्रदेश सरकार)—

इस योजना में शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका सुधार पर जोर दिया गया है, परंतु स्थानीय स्तर पर इसका शैक्षणिक प्रभाव सीमित देखा गया है।

5. सामाजिक दृष्टिकोण और शिक्षा के प्रति रुझान— बहराइच की जनजातियों में शिक्षा को लेकर दृष्टिकोण अभी भी मिश्रित है। अभिभावक बालकों को आर्थिक सहायता के लिए खेतों या मजदूरी में लगाना अधिक उचित समझते हैं। बालिकाओं की शिक्षा को अक्सर आवश्यक नहीं माना जाता। विद्यालय की दूरी और सुरक्षा की चिंता के कारण कई माता-पिता बेटियों को विद्यालय नहीं भेजते। हालाँकि, कुछ क्षेत्रों में एनजीओ और स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित शिक्षा जागरूकता अभियानों से बदलाव की शुरुआत हुई है।

6. क्षेत्रीय अंतर और लैंगिक विषमता—

- i. क्षेत्रीय अंतर— मिर्हीपुरवा और नानपारा ब्लॉक के विद्यालयों में उपस्थिति दर 60–65% तक है, जबकि कैसरगंज और रूपैडिहा क्षेत्रों में यह 75% तक पहुँचती है।
- ii. लैंगिक अंतर— जनजातीय लड़कों की साक्षरता लगभग 54%, जबकि लड़कियों की 46% के आसपास है। विवाह—प्रथा, घरेलू कार्यों में संलिप्तता, और बाल विवाह जैसी प्रथाएँ बालिकाओं की शिक्षा में बाधक हैं।

बहराइच जनपद में जनजातीय शिक्षा की प्रमुख समस्याएँ—

1. आर्थिक समस्याएँ— अधिकांश जनजातीय परिवार दैनिक मजदूरी, वनोपज संग्रह या कृषि पर निर्भर हैं। परिवारों की आय इतनी कम है कि वे बच्चों की फीस, पुस्तकों या यूनिफॉर्म का खर्च नहीं उठा पाते। कई बच्चे परिवार की आय में सहयोग हेतु खेतों या निर्माण कार्यों में लग जाते हैं। गरीबी और ऋणग्रस्तता शिक्षा को द्वितीय स्थान पर रखती है।
2. भौगोलिक और संरचनात्मक समस्याएँ— बहराइच का उत्तरी भाग वनाच्छादित है, जहाँ गाँव बिखरे हुए हैं। विद्यालयों की दूरी अधिक होने के कारण बच्चों को प्रतिदिन 3–4 किमी पैदल चलना पड़ता है। बरसात के मौसम में सड़कों का अभाव स्कूल पहुँचने में बड़ी बाधा बनता है। कुछ विद्यालयों में छत या बेंच जैसी मूलभूत सुविधाएँ तक नहीं हैं।
3. शिक्षकों की अनुपलब्धता और गुणवत्ता की समस्या— जनजातीय क्षेत्रों में प्रशिक्षित शिक्षकों की भारी कमी है। कई शिक्षक गैर-जनजातीय पृष्ठभूमि से आते हैं, जिन्हें स्थानीय संस्कृति या भाषा की जानकारी नहीं होती। इससे शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संवाद का अभाव रहता है। निरीक्षण और निगरानी की व्यवस्था भी कमजोर है, जिससे उत्तरदायित्व कम रहता है।
4. भाषाई और सांस्कृतिक असंगति— थारू समुदाय के बच्चे घर पर थारू भाषा बोलते हैं, जबकि विद्यालयों में शिक्षण हिंदी या अंग्रेजी में होता है। भाषा की यह बाधा उन्हें शिक्षा से दूर करती है। पाठ्यक्रम में स्थानीय संस्कृति, लोककथाएँ या पारंपरिक ज्ञान शामिल न होने से बच्चे अपने परिवेश से जुड़ाव महसूस नहीं करते।
5. सामाजिक-सांस्कृतिक और मानसिक समस्याएँ— शिक्षा के प्रति परिवारिक रुचि कम है। बालिकाओं को शिक्षा के बजाय पारिवारिक दायित्वों में लगाया जाता है। सामाजिक रुढ़ियाँ, जैसे – “लड़कियों का पढ़ना व्यर्थ है” – अभी भी प्रचलित हैं। कुछ विद्यार्थियों को विद्यालय में भेदभाव या उपेक्षा का अनुभव होता है, जिससे उनका आत्मविश्वास घटता है।

6. सरकारी योजनाओं से जुड़ी सीमाएँ— योजनाएँ तो अनेक हैं, परंतु क्रियान्वयन में कमजोरी है। छात्रवृत्तियाँ समय पर नहीं मिलतीं, स्कूलों में निरीक्षण नहीं होता। योजनाओं की जानकारी न होने से अभिभावक लाभ नहीं उठा पाते। स्थानीय प्रशासन और शिक्षा विभाग के बीच समन्वय का अभाव देखा गया है।
7. आधारभूत सुविधाओं की कमी— विद्यालय भवनों की स्थिति जर्जर है। साफ पेयजल, शौचालय, खेलकूद मैदान, और कंप्यूटर सुविधाएँ नहीं हैं। बालिकाओं के लिए अलग शौचालय न होने के कारण उनकी उपस्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

समाधान एवं सुझाव –

1. आर्थिक सुधार के उपाय –

- i. सभी जनजातीय विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की गारंटी— प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक, छात्रवृत्ति योजनाओं को समय पर और पारदर्शी तरीके से वितरित किया जाए।
- ii. मुफ्त पाठ्यसामग्री और पोषणयुक्त भोजन—सभी विद्यालयों में किताबें, यूनिफॉर्म और मिड-डे मील की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए ताकि अभिभावक आर्थिक रूप से बोझ महसूस न करें।
- iii. परिवारों के लिए आजीविका सहायता कार्यक्रम— जनजातीय परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु स्व-सहायता समूह कौशल विकास और सूक्ष्म वित्त योजनाएँ बढ़ाई जाएँ। इससे बच्चों को श्रम कार्यों में लगने के बजाय शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

2. भौगोलिक और अवसंरचनात्मक सुधार –

1. नजदीकी विद्यालयों की स्थापना— दुर्गम और वनवर्ती क्षेत्रों में छोटे आकार के प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जाएँ, ताकि बच्चों को दूर न जाना पड़े।
2. परिवहन सुविधा— विद्यालय तक पहुँच के लिए सस्ती बस या साइकिल सहायता योजनाएँ शुरू की जाएँ।
3. विद्यालय भवन और संसाधनों में सुधार— प्रत्येक विद्यालय में स्वच्छ पेयजल, बालिकाओं हेतु पृथक शौचालय, पुस्तकालय और खेल सामग्री अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए।
4. डिजिटल शिक्षा का विस्तार— 'ई-पाठशाला', और स्थानीय रेडियो शिक्षा कार्यक्रमों को जनजातीय ब्लॉकों तक पहुँचाया जाए। मोबाइल-आधारित शिक्षा से बच्चों तक शिक्षा को सुलभ बनाया जा सकता है।

3. शैक्षणिक सुधार –

1. स्थानीय भाषा आधारित शिक्षण— थारु और अन्य जनजातीय भाषाओं में शिक्षण सामग्री तैयार की जाए। प्रारंभिक कक्षाओं में मातृभाषा को शिक्षण माध्यम बनाया जाए ताकि बच्चों की समझ और रुचि दोनों बढ़ें।
2. शिक्षक प्रशिक्षण और स्थानीय नियुक्ति— जनजातीय क्षेत्रों में नियुक्त शिक्षकों को स्थानीय संस्कृति और भाषा का प्रशिक्षण दिया जाए। साथ ही स्थानीय समुदाय के योग्य युवाओं को शिक्षक के रूप में प्राथमिकता दी जाए।
3. पाठ्यक्रम का स्थानीयकरण— शिक्षा में थारु जनजाति की संस्कृति, लोककथाएँ, लोककला, और पारंपरिक ज्ञान को शामिल किया जाए ताकि बच्चे अपनी संस्कृति पर गर्व महसूस करें।
4. अभिनव शिक्षण पद्धतियाँ— पारंपरिक रट्टा प्रणाली के बजाय परियोजना-आधारित, अनुभवात्मक और व्यावहारिक शिक्षा अपनाई जाए।

4. सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार—

1. सामुदायिक सहभागिता— विद्यालय प्रबंधन समितियों में अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। ग्राम सभाओं में शिक्षा पर चर्चा अनिवार्य की जाए।
2. बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान— बालिका छात्रावास, सुरक्षित परिवहन और विशेष छात्रवृत्ति योजनाएँ चलाई जाएँ। "बेटी पढ़ाओ—बेटी बचाओ" अभियान को जनजातीय बस्तियों में सशक्त किया जाए।
3. शिक्षा जागरूकता अभियान— स्थानीय धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजनों के माध्यम से शिक्षा के महत्व पर संवाद चलाया जाए।
4. सांस्कृतिक एकीकरण— शिक्षा में स्थानीय उत्सव, लोकनृत्य, लोकगीत आदि को शामिल करने से बच्चों का विद्यालय से लगाव बढ़ेगा।

5. प्रशासनिक और नीतिगत सुधार—

1. योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन— समग्र शिक्षा अभियान, एकलव्य विद्यालय, और थारु विकास योजना की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए।
2. जवाबदेही प्रणाली— शिक्षकों की उपस्थिति, विद्यार्थियों की प्रगति और योजनाओं के उपयोग की निगरानी के लिए डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया जाए।
3. स्थानीय शासन की भूमिका— ग्राम पंचायतों को विद्यालयों की निगरानी और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सीधा अधिकार दिया जाए।
4. गैर—सरकारी संगठनों की भागीदारी— शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय एनजीओ, जैसे 'प्रथम', 'एजुकेशन अलायंस' आदि को बहाराइच के जनजातीय क्षेत्रों में साझेदारी के रूप में शामिल किया जा सकता है।
6. मनोवैज्ञानिक और प्रेरणात्मक सुधार— शिक्षकों को विद्यार्थियों के साथ संवेदनशील व्यवहार के लिए प्रशिक्षित किया जाए। विद्यालयों में परामर्श केंद्र स्थापित किए जाएँ, जो विद्यार्थियों के आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य पर काम करें। "रोल मॉडल" प्रणाली शुरू की जाए, जिसमें सफल जनजातीय युवाओं को स्कूलों में आमंत्रित कर प्रेरणा दी जाए।

निष्कर्ष एवं सिफारिशें —

1. समग्र निष्कर्ष— शोध के निष्कर्ष बताते हैं कि जनपद बहाराइच में जनजातीय शिक्षा की स्थिति सुधार की दिशा में अग्रसर तो है, लेकिन चुनौतियाँ अब भी विद्यमान हैं। जनजातीय समुदायों में शिक्षा की मुख्य बाधाएँ — गरीबी, दूरी, भाषा, सांस्कृतिक असमानता, तथा सरकारी योजनाओं के कमजोर क्रियान्वयन हैं। जहाँ स्थानीय भाषा में शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता और छात्रवृत्ति योजनाएँ सशक्त हैं, वहाँ शैक्षणिक परिणाम बेहतर देखे गए हैं।

2. सिफारिशें —

1. स्थानीय स्तर पर शिक्षा नीति का पुनरीक्षण— जिला शिक्षा विभाग को जनजातीय प्रतिनिधियों के साथ मिलकर वार्षिक शिक्षा योजना तैयार करनी चाहिए।
2. थारु संस्कृति पर आधारित पाठ्यक्रम— थारु जनजाति की कहानियों, इतिहास और कला को शिक्षा में सम्मिलित कर बच्चों का आत्म-सम्मान बढ़ाया जा सकता है।

3. लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष प्रोत्साहन— स्कॉलरशिप, सुरक्षित छात्रावास, और महिला शिक्षकों की नियुक्ति बढ़ाई जाए।
4. शिक्षकों की स्थानीय भर्ती और प्रशिक्षण— इससे शिक्षक—विद्यार्थी के बीच सांस्कृतिक अंतर कम होगा और संवाद बेहतर बनेगा।
5. सामाजिक जागरूकता अभियान— गाँव स्तर पर अभिभावकों को यह समझाया जाए कि शिक्षा ही दीर्घकालिक आर्थिक सशक्तिकरण का साधन है।

3. अंतिम विचार— जनजातीय शिक्षा का सुधार केवल योजनाओं से नहीं बल्कि समाज, सरकार और समुदाय की साझा जिम्मेदारी से संभव है। जब जनजातीय समुदाय स्वयं शिक्षा की प्रक्रिया का भाग बनेंगे, तब ही वास्तविक परिवर्तन आएगा। बहराइच की जनजातियाँ सांस्कृतिक रूप से सशक्त हैं — यदि शिक्षा को उनकी संस्कृति से जोड़ा जाए, तो यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए आदर्श बन सकता है।

संदर्भ सूची—

1. भारत सरकार (2011). जनगणना सारांश भारत सरकार।
2. भारत सरकार (2023). एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. उत्तर प्रदेश सरकार (2022). थारू जनजाति विकास रिपोर्ट, जनजातीय कार्य विभाग, लखनऊ।
4. कुमार, — सिंह, पी. (2019). भारत में जनजातीय शिक्षा की चुनौतियाँ. इंडियन जर्नल ऑफ एजुकेशन, 14(2), 45–60।
5. राय, एस., — वर्मा, ए. (2021). उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति की शिक्षा की स्थिति. जर्नल ऑफ सोशल एंड ट्राइबल स्टडीज, 9(3), 22–38।
6. अंशुमान, आर., — गुप्ता, वी. (2020). जनजातीय शिक्षा और सामाजिक समावेशन. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज, 16(1), 10–25।
7. UDISE Data Portal (2022). District Education Dashboard Bahraich Uttar Pradesh-